(a) whether Government propose to amend the laws governing foreign investment in power sector;

(b) if so, the details thereof;

(c) whether some of the American Power Companies have refused to invest in India unless the tax-free status is provided to the power sector;

(d) whether a number of foreign firms have also demanded the same; and

(e) whether Government have taken a final decision in this regard, and if not, the reasons therefor ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF POWER (SHRI P. V. RANGAYYA NAIDU) : (a) No Sir.

(b) Does not arise.

(c) and (d) No Sir.

(e) Does not arise.

THREATS OF TERRORIST OUTFITS AGAINST THE EXCUTION OF DULHASTI PROJECT

2661. DR. MURLI MANOHAR JOSHI:

SHRI TRILOKI NATH CHATURVEDI : Will the Minister of Power be pleased to refer to the answer to Unstarred Question 580 given in the Rajya Sabha on the 7th December, 1993 and state :

(a) what was the original cost of Dulhasti Project;

(b) whether the terrorist outfits have issued threats against the execution of this project; if so, the details thereof; and

(c) what are the details of the present status of the project ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF POWER (SHRI P. V. RANGAYYA NAIDU) : (a) The Dulhasti Hydro-electric Project was sanctioned in July 1989 at an estimated cost of Rs. 1262.97 crore (including interest during construction) for execution through a French Consortium.

(b) In July 1993, the French Consortium received a warning through the press from terrorists of severe punishment in case the work at the Project was not stopped.

(c) Work at the project site had been suspended by the French Consortium in August 1992 on grounds of security. Till then most of the infrastructural work and about 27 per cent of the major civil works had been completed. About 75 per cent of the work relating to engineering and design and preparation of detailed construction drawings has also been completed. The Consortium have supplied about 28 per cent of the electro-mechanical equipment and another 50 per cent of the equipment is ready for shipment.

संसद सदस्यों द्वारा मंत्रालय को भेजे गए पत्र

2662. **श्री मोहम्मद अफजल उर्फ भीम अफजल** : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) संसद सदस्यों द्वारा मंत्रालय को 1-4-90 से 31-3-93 की अवधि के दौरान लिखे गए पत्रों का वर्षवार ब्यौरा क्या है;

(ख) इन पत्रों में से कितने पत्रों की पावती भेजी गई,

(ग) कितने पत्रों के अंतिम उत्तर भेजे गए, और

(घ) मंत्रालय द्वारा भेजे गए इन अंतिम उत्तरों में से कितने पत्रों के उत्तर सकारात्मक थे और कितने नकारात्मक ?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. वी. रंगैया नायडु) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान

विद्युत् मंत्रालय में संसद सदस्यों से प्राप्त पत्रों की संख्या का ब्यौरा निम्नवत् है :--

1990-91	554
1991-92	687
1992-93	772
कुल	2013

(ख) उपरोक्त में से 2008 पत्रों की पावती भेजी गई थी।

(ग) और (घ) 752 पत्रों के उत्तर नकारात्मक और 630 पत्रों के उत्तर सकारात्मक सहित कुल 1650 पत्रों के अंतिम उत्तर भेजे गए थे।

PROVIDING ASSURED RATE OF RETURN TO FOREIGN INVESTORS

2663. SHRI ASHOK MITRA : Will the Minister of Power be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Government propose to provide a 16 per cent assured rate of return in dollar terms to foreign investors in the power seitor.

(b) if so, the procedure of assessment of cost and the mechanism of pricing in terms of which such a rate of return is proposed to be ensured; and

(c) the average cost per megawatt in the foreign investment projects approved so far, and the corresponding cost per megawatt of power projects completed in the country over the past five years ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF POWER (SHRI P. V. RANGAYYA NAIDU)) : (a) and (b) The 16 per cent return on equity which will be denominated in dollars in case of foreign equity only would be an element in the fixed cost part of the tariff for generating companies.

(c) The average cost per MW involving foreign investment has been established only in so far as the gas based projects are concerned and is estimated at present at Rs. 3.65 crores per MW at 1996 price level. The cost per MW of such projects completed during the last 5 years was between Rs. 1 crore per MW to Rs. 2.4 crores per MW.

बिहार में बिजली उत्पादन

2664. श्री ब्रह्मदेव आनन्द पासवान : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या "दामोदर घाटी निगम" से उत्पन्न बिजली को बिहार के बाहर ले जाया जा रहा है;

(ख) क्या झुमरी तलैया, कोपार्क, सामधान और पोत बांधों से उत्पन्न बिजली को भी बिहार से बाहर ले जाया जा रहा है;

(ग) क्या बिहार का कोयला, ताम्बा, अभ्रक, एल्यूमिनियम, जस्ता का भरपूर दोहन करने के लिए तसाम विद्युत् चालित रेलें दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता की शान बढ़ा रही हैं जबकि पूरा बिहार बिजली के बिना अंधकार में डूबा हुआ है;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार बिहार को आवश्यक मात्रा में बिजली प्रदान करने का विचार रखती है ताकि वहां उद्योगों को बढ़ावा मिल सके; और

(ङ) यदि हां, तो प्रत्येक दिन कितनी बिजली दिए जाने की सम्भावना है और कब तक ?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.वी. रंगैया नायडु) : (क) से (ङ) दामोदर घाटी निगम प्रणाली में उत्पादित विद्युत् को बिहार व पश्चिम बंगाल राज्य और बड़े उपभोक्ताओं जैसे रेलवे, स्टील, कोयला आदि को एक निर्धारित फार्मूला के अनुसार आवंटित किया जाता है। बिहार अपने बकाया हिस्से की दामोदर घाटी निगम प्रणाली और दूसरे केन्द्रीय विद्युत् उत्पादन, केन्द्रों दोनों से प्राप्य करने के लिए अधिकृत है। केन्द्रीय विद्युत् उत्पादक एजेंसियां, राज्य बिजली बोर्डों को बड़ी मात्रा में विद्युत् की आपूर्ति करते हैं और अनेक उपभोक्ताओं जैसे उद्योगों को विद्युत् का वितरण करना, राज्य बिजली बोर्डों की जिम्मेवारी है। बिहार राज्य में विद्युत् की अपर्याप्त आपूर्ति के लिए, बिहार राज्य का विद्युत् संयंत्र का घटिया कार्य निष्पादन मुख्य रूप से उत्तर दायी रहा है। वर्ष 1992-93 के